भारी दुर्दशा का शिकार सेक्टर 8 का अस्पताल व इसकी डिस्पेंसरियां

सेक्टर 8 के 200 बेड की इमारत ईएसआईसी ने बना कर हरियाणा सरकार को सौंप दी थी। बरसों वीरान पड़ी रहने के बाद सन् 1993 में यहां अस्पताल चालू किया गया वह भी मात्र 50 बेड का और उसके लिये भी न तो स्टाफ़ पर्याप्त है न कोई साज-ओ-सामान। इसलिये इन 50 बेडों पर भी आकर कोई लेटने को तैयार नहीं।

धूर्तों व मूर्खों द्वारा चलाई जा रही हरियाणा सरकार कह सकती है कि अच्छा किया जो इसमें 200 बेड नहीं लगाये वरना वे भी खाली ही पड़े रहते। हरामखोरों के लिये काम न करने व अपनी जनता को धोखा देने के लिये यह तर्क अच्छा हो सकता है। परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है। जब वहां सौदा ही कुछ नहीं रखा तो कोई वहां लेने क्या आयेगा? एक बार वहां पर्याप्त आवश्यक स्टाफ़ व साज-ओ-सामान रख कर देखे सरकार, 50 तो क्या 200 बेड भी कम पड़ेंगे, जैसे कि एनएच-3 में पड़ रहे हैं।

मजे की बात तो यह है कि हरियाणा सरकार के घर से कुछ खास नहीं जाना; कुल खर्च का मात्र 12 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा व शेष 88 प्रतिशत ईएसआईसी द्वारा खर्च किया जाता है। राज्य सरकार अपना 12 प्रतिशत बचाने के चक्कर में ईएसआई से मिलने वाला 88 प्रतिशत छोड़ देती है, जबकि ईएसआईसी इस राज्य से करीब 3000 करोड़ हर साल वसूल कर अपने खजाने को लगातार बढाये जा रही है।

इस अस्पताल से भी बद्तर हालत तमाम 12 डिस्पेंसरियों की है। पहले तो डिस्पेंसरियों की यह संख्या ही आवश्यकता से बहुत कम है; दूसरे इनमें न तो स्टाफ़ है न कोई आवश्यक उपकरण और जो स्टाफ़ है उसका माहौल इतना बिगाड़ रखा है कि वहां कोई काम ढंग से होता नहीं। डॉक्टर साहब का जब दिल करे आ-जायें न करे तो न भी आयें कोई पूछने वाला नहीं। व्यवस्था ऐसी है कि जहां मरीज़ों की संख्या कम है वहां डॉक्टर ज़्यादा, ताकि उन्हें बारी-बारी फ़रलों मारने में दिक्कत न हो।

एमसीआई बनाम ईएसआईसी

एमसीआई यानी मेडिकल काऊंसिल ऑफ़ इन्डिया, वह संस्था है जिसका कर्त्तव्य देश भर के तमाम चिकित्सा संस्थानों-अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों आदि पर कड़ी नज़र रखना है। इसका कर्त्तव्य है कि यह सुनिश्चत करे कि तमाम चिकित्सा संस्थान तय मानकों के अनुसार चल रहे हैं। इसके लिये एमसीआई के पास पर्याप्त अधिकार हैं। परन्तु इसके पास इतनी फ़ुर्सत नहीं कि यह देश भरके तमाम अस्पतालों का निरीक्षण करके कोई कार्यवाही कर सके।

कार्यवाही करने भी लगे तो किसके खिलाफ़? तय मानकों की सबसे ज्यादा ऐसी-तैसी तो खुद सरकार तथा इसके निगमों द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में की जा रही है। ऐसे में एमसीआई सरकार से उलझने के बजाय मेडिकल कॉलेज तक ही सीमित रहती है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में तो कोई खास कमियां रहती नहीं है और जो रहती भी हैं तो उन्हें दूर करने का आश्वासन सरकार द्वारा दिये जाने के बाद एमसीआई शान्त हो जाती है; जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में तमाम कमियां सदैव रहती हैं। जिसके बदले एमसीआई वालों को मोटी घूस मिलती है।

ईएसआईसी भी लगता है मेडिकल कॉलेज बना कर फ़ंस गयी है। इसके अस्पतालों में जो मानक खुद इसने ही तय कर रखे हैं, उन्हें भी यह पूरा नहीं कर रही है, हां एमसीआई के डंडे से जरूर रो-पीट कर यह उन मानकों को पूरा करती है जिनके न करने पर मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हो सकती है। बस एमसीआई के इसी डंडे के चलते मज़दूरों को इस अस्पताल में राहत मिल पा रही है। इसी 'फ़जीहत' से बचने के लिये ईएसआईसी के कुछ निकम्मे व हरामखोर अफ़सर कभी भी मेडिकल कॉलेज खोलने के हक में नहीं रहे। उनका बस चले तो वे अभी भी तमाम मेडिकल कॉलेजों को बंद करके या किसी को देकर अपना पिंड छुड़ाना चाहेंगे।

ब्लड बैंक

जनवरी 2018 यानी इसी माह से यहां ब्लड बैंक चालू होने जा रहा है। इसके लिये आवश्यक लाइसेंस व काम चलाऊ स्टाफ़ व उपकरण मिल चुके हैं। पूरे हरियाणा में इसके मुकाबले का ब्लड बैंक नहीं है। फ़िलहाल इस बैंक से शल्य चिकित्सा के लिये आवश्यक खून की जरूरत पूरी की जा सकेगी। लेकिन आगामी 6-7 माह में अन्य उपकरण व स्टाफ़ के आ जाने पर यहां प्लेटलेट्स, विभिन्न प्रकार के प्लाजमा आदि भी उपलब्ध होने से डेंगू व अन्य गम्भीर बीमारियों के इलाज हेतु मरीज़ों को निजी अस्पतालों की ओर नहीं दौड़ना पड़ेगा।

विदित है कि फ़िलहाल इस औद्योगिक नगरी में कोई भी सही ढंग का ब्लड बैंक नहीं है। बीके अस्पताल वाला तो कतई बेकार है। निजी अस्पतालों में भी जो हैं वे महज कामचलाऊ से ही हैं और बहुत महंगे पड़ते हैं। इन अस्पतालों में मरीज़ के परिजनों से खून के बदले खून तो लिया ही जाता है साथ में अच्छे खासे पैसे भी लिये जाते हैं। जबकि ईएसआई के इस अस्पताल में ऐसा कुछ नहीं होगा। मज़दूरों के लिये यह एक बहुत बड़ी राहत होगी।

अलवर के उपचुनाव में ईएसआईसी

अलवर के भाजपा सांसद महंत चांद नाथ जिनके विरुद्ध अपने गुरू महंत आजाद नाथ की हत्या का मुकदमा थाना बावल में दर्ज हुआ था, के मरने से रिक्त स्थान को भरने के लिये वहां शीघ्र ही उपचुनाव होने जा रहा है, वहां के मतदाताओं को बेवकूफ़ बनाने के लिये भारत की मोदी सरकार ने बरसों से बंद पड़े वहां के मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चालू करने का नाटक शुरू कर दिया है।

फ़रीदाबाद से भी पहले वहां का मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुआ था। करीब 800 करोड़ की लागत से ईएसआई कार्पोरेशन ने इसकी इमारत बना कर खड़ी कर दी और ताला मार दिया। अब चुनावी जनसभाओं में मोदीजी व उनके अन्य भोंपू जनता को बतायेंगे कि वे इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चालू करने जा रहे हैं। करीब 700 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में फ़िलहाल 50 बिस्तरों का एक दिखावटी सा अस्पताल चलाने के लिये फ़रीदाबाद से डॉ. गौतम को एमएस (मेडिकल सुपरिंटेंडेंट) बना कर भेज दिया गया है।

विदित है कि फ़रीदाबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चलाने में जितने रोड़े वे अटका सकते थे, उन्होंने अटकाये; बेशक यह काम वे मुख्यालय में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर ही करते थे। प्रशासनिक पद पर होने के नाते उन्हें ढेरों फ़ाइलों पर दस्तखत करने होते थे, जिन्हें करने से वे हमेशा गुरेज करते थे। उनके तबादले से यहां के अस्पताल व कर्मचारियों को कुछ राहत की सांस मिलेगी।

ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल: संघर्ष से बहुत सुधरा, कमियां भी बरकरार

फ़रीदाबाद (म.मो.) मज़दूर संगठनों द्वारा दसियों वर्ष के संघर्ष उपरान्त एनएच-3 स्थित अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित करने के बाद अब यहां मज़दूरों एवं उनके आश्रितों को कुछ राहत मिलती नज़र आने लगी है। अस्पताल की, करीब 48 साल पुरानी व अपर्याप्त हो चुकी इमारत को लगभग पूरी तरह से खाली करके सब कुछ नई वातानुकूलित इमारत में शिफ़्ट कर दिया गया है।

ओपीडी में पहले जहां मरीज़ों की लम्बी लगी लाइनों में खड़े होने तक जगह नहीं थी वहां अब आराम से वातानुकूलित जगह में बैठने की व्यवस्था है। अतिरिक्त काऊंटर खुलने से मरीज़ों की लम्बी कतारें भी काफ़ी छोटी हुई हैं। डॉक्टरों की कुल संख्या जहां घटते-घटते 30 तक रह गयी थी वहां अब विशेषज्ञ फेकल्टी तथा रेजिडेंट डॉक्टरों सहित 200 से ऊपर पहुंच गयी है जो मरीज़ों की बढती संख्या को देखते हुए अभी भी कम है। नर्सों की संख्या 40 से बढकर 200 हो गयी जो अभी भी कम पड़ रही है।

नई इमारत में इमरजेंसी के 30 बेड, आईसीयू के 30 बेड, लेबर रूम के 18 बेड, शिशु नर्सरी के 30 बेड, डालेसिस के 16 बेड के अतिरिक्त विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीज़ों के लिये 380 बेड हैं और ये सभी फुल रहने की वजह से अपर्याप्त लग रहे हैं।

जर्जर हो चुकी 34 साल पुरानी एक्सरे मशीन की जगह 2 नई एवं आधुनिक डिजिटल मशीनें चालू हो चुकी हैं तथा 2 और भी जल्द आने वाली हैं। इकलौती अल्ट्रासाऊंड मशीन के चलते जो मरीजों को लम्बी तारीख देकर भटकाया जाता था वहां अब 2 अतिरिक्त नई मशीनें चालू होने से मरीज़ों को काफ़ी राहत मिली है, इसके बावजूद 2 और मशीनों की कमी खल रही है जिसे पूरा करने के प्रयास जारी हैं।

डायलेसिस कराने वाले मरीज़ों को अब व्यापारिक अस्पतालों के चक्कर काटने से कुछ राहत मिल जायेगी। कुछ इसलिये कि यहां जो डायलेसिस का काम शुरू किया गया है व पीपीपी मोड में किसी ठेकेदार को दिया गया है। वास्तव में इस काम के लिये पूरा नेफ़रोलॉजी विभाग एवं नेफ़रोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत होती है जो मुनाफ़े का धंधा करने वाले ठेकेदार कर ही नहीं सकते। इसलिये हाल-फ़िलहाल यह विभाग कामचलाऊ राहत तो दे सकता है परन्तु पूरा इलाज नहीं। सीटी स्कैन व एमआरआई के लिये पीपीपी मोड में ठेकेदार ढूंढने में असफ़ल रहने के बाद अब ईएसआई कार्पोरेशन के नालायक उच्चाधिकारियों को समझ आ गयी है कि ये उपकरण तो उन्हें खुद ही खरीदने पड़ेंगे। करीब 25 करोड़ की लागत के इन उपकरणों के लिये टेंडर आमंत्रित कर लिये गये हैं। यदि उक्त नालायक अधिकारियों की नीयत ठीक रही तो जुलाई या अगस्त 2018 तक ये उपकरण भी यहां चालू हो जायेंगे।

नई इमारत में 8 बड़े व 4 छोटे ओटी (ऑप्रेशन थियेटर) तो बन कर तैयार हो चुके है जबकि पुरानी इमारत में केवल एक ही था और वह भी बेकार सा। परन्तु अभी चालू केवल 2 ही कर पाये हें क्योंकि सभी ओटी को चलाने के लिये अभी भी न तो पर्याप्त स्टाफ़ है और न ही उपकरण। इसके चलते हड्डियों वाले विभाग में मरीज़ों की लम्बी प्रतिक्षा सूची चल रही है। इससे मरीज़ों का परेशान होना स्वाभाविक है।

एक ओटी की व्यवस्था इमरजेंसी में भी रखी गयी है जो कि स्टाफ़ एवं सामान के आभाव में अभी तक चालू नहीं हो सका। इसके चालू हो जाने का मतलब होता है कि कोई भी मरीज़ फ़ैक्ट्री या सड़क दुर्घटना में टूट-फूट कर आता है तो उसे रात या दिन (चौबीस घंटे) कभी भी, सर्जरी सहित पूरा इलाज दिया जा सकता है। इसके बरक्स अब ऐसे मरीज़ों को रूटीन मरीज़ों की कतार में डाल देना पड़ता है। इन हालात में कोई भी दुर्घटनाग्रस्त ईएसआई के इस अस्पताल में आने की अपेक्षा किसी व्यापारिक अस्पताल में जाना अधिक पसंद करता है।

मैटरनिटी यानी जच्चा-बच्चा विभाग में काफ़ी सुधार के चलते यहां होने वाली डिलिवरियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। लेकिन वास्तविक आवश्यकता से यह अभी भी बहुत कम है। पहले पुरानी इमारत में जहां ओस्तन 40 डिलिवरी प्रति माह होती थीं वहीं अब यह संख्या 100 से अधिक हो गयी है। फ़िलहाल इसकी क्षमता 400 डिलिवरी प्रति माह की है जबकि ईएसआई कार्ड होल्डरों की संख्या (करीब 8 लाख) को देखते हुए यह क्षमता 800 प्रति माह यानी डबल होनी चाहिये। मुख्यालय में बैठे उच्चाधिकारी अभी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं; इसके लिये अलग से संघर्ष करना पड़ेगा। इतना कुछ होने के बावजूद आज भी 800 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में 13 फेकल्टी विशेषज्ञ डॉक्टरों, 250 पैरामेडिकल, 250 स्टाफ़ नर्स, 150 दफ़तरी व अन्य स्टाफ़ के अलावा 50 रेज़िडेंट डॉक्टरों की कमी है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि मुख्यालय में बैठ कर मोटी तनख्वाहें डकार रहे उच्चाधिकारी अभी तक 250 स्टाफ़ नर्स सिलेक्ट नहीं कर सके जबकि 18000 नर्सों ने करीब 2 वर्ष पूर्व नौकरी के लिये आवेदन किया था।

दरअसल इन उच्चाधिकारियों की नीयत एवं रूची अस्पताल चलाने की बजाय बीमा कार्पोरेशन चलाने की रहती है। इनकी सोच तमाम मरीज़ों को सही एवं सहज उपचार देने की अपेक्षा व्यापारिक अस्पतालों में रैफ़र करने की रहती है। इसमें इन्हें काम तो कुछ खास करना नहीं पड़ेगा और व्यापारिक अस्पतालों से बतौर कमीशन, घर बैठे मोटी कमाई होती। इतना भारी-भरकम अस्पताल बनाने के बावजूद आज भी 10-15 करोड़ रुपया व्यापारिक अस्पतालों को रैफ़र हुए मरीज़ों के बिल भुगतान हेतु देना पड़ रहा है।

गौरतलब बात यह भी है कि देश भर में मज़दूरों से, उनके वेतन का साढे छः प्रतिशत वसूल-वसूल कर ईएसआई कार्पोरेशन ने आज अपने खजाने में 75 हज़ार करोड़ रुपये भर लिया है; उसके बावजूद स्टाफ़ की कमी क्यों रखी जाती है जबकि हर तरह के ट्रेंड बेरोजगारों की फ़ौज यहां धक्के खाती घूम रही है? इसी तरह आज बाज़ार में हर तरह का उपकरण व साजो-सामान उपलब्ध है व्यापारिक अस्पताल बैंकों से कर्ज ले-लेकर उन्हें खरीदते हैं तो ईएसआई निगम को क्या मौत पड़ती है यह सब खरीदने में ?

सरकार एवं निगम की सोच यह रहती है कि जब बिना स्टाफ़ और उपकरणों के काम चलाया जा सकता है तो इनको लगाने की जरूरत ही क्या है? तर्क बेहूदा होने के बावजूद बड़ा सटीक है। नई इमारत बनने से पहले पुरानी इमारत में भी तो काम चल ही रहा था; यदि यह नया मेडिकल कॉलेज अस्पताल न बनता तो भी तो काम चलता ही रहता। पुराने और नये अस्पताल के साथ काम-काज का अन्तर साफ़ नज़र आ रहा है। पहले जहां 1200-1400 मरीज़ ओपीडी में आते थे अब 1800-2000 आने लगे हैं। पहले जहां 200 बेड भी पूरे नहीं भरते थे अब 500 भी कम पड़ रहे हैं। जाहिर है पहले केवल वही मरीज़ ईएसआई में इलाज कराने का जोखिम उठाते थे जिनके पास और कोई विकल्प नहीं था। यह तथ्य आज स्वत: सिद्ध हो रहा है। लगभग यही स्थिति गुड़गांव व अन्य शहरों की है। यदि ईएसआई स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाय तो मज़दूर अपने दिये गये पैसे का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

नौ महीने से कागजों में चल रहा है एनसीडी क्लीनिक

फ़रीदाबाद। (म.मो.) जिला सिविल सर्जन डॉ. गुलशन अरोड़ा सरकारी फंड को ऐंठने के लिए न केवल सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं बल्कि वे आम जनता की पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। अप्रैल 2017 में राज्य सरकार ने बादशाह खान अस्पताल में एनसीडी (नॉन कम्युनिकेटिड डिजिजस क्लीनिक) क्लीनिक खोलने के आदेश दिए थे। लेकिन डॉ. अरोड़ा क्लीनिक को शुरू करने की बजाए इसे कागजों में चलाते रहे हैं।

लेकिन डॉ. अरोड़ा के हाथ पैर उस समय फूल गए जब उन्हें स्वास्थ्य मुख्यालय से सूचना मिली कि टीम 21 दिसंबर को इस क्लीनिक का दौरा करने के लिए आ रही है। डॉ. गुलशन अरोड़ा के आदेश पर कर्मचारियों ने 20 दिसंबर को डीईआईसी सेन्टर के एक कमरे के बाहर आनन फानन में एनसीडी क्लीनिक का बोर्ड लगा कर खानापूर्ति कर दी।

बदलती जीवनशैली और खानपान में आए बदलाव के कारण लोग हृदयरोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इस तरह की बीमारियों से अब ग्रामीण इलाकों के लोग भी अछूते नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों में भी यह बीमारियां तेजी से पांव पसार रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानी कैंसर के मरीजों को हो रही है। उन्हें अपने इलाज के लिए रोहतक पीजीआई के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिले के बादशाह खान अस्पताल, सीएचसी खेड़ीकलां व कौराली और बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में एनसीडी क्लीनिक खोलने के आदेश दिए थे। इन क्लीनिकों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप व हृदयरोग के इलाज के साथ साथ ही यहां कैंसर के मरीजों को

रेडिएशन व कीमोथेरेपी की सुविधा भी यहीं पर देने की योजना बनाई गई थी। एनसीडी क्लीनिकों में सरकार ने अनुबंध के आधार पर डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती करने के आदेश भी दिए थे। प्रत्येक क्लीनिक में दो नर्सिंग स्टॉफ, आठ जीएनएम, एक मेडिकल ऑफिसर, एक फिजिशियन, एक अकाउंटेंट और एक सूचना सहायक की नियुक्ति करने के आदेश दिए थे। इसकी भर्ती के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने 22 व 25 मार्च 2016 को आवेदकों के साक्षात्कार भी लिए थे। लेकिन अब तक मात्र दो जीएनएम और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा एनसीडी क्लीनिक के लिए कोई भर्ती नहीं की। अप्रैल 2017 में क्लीनिकों को शुरूआत करने बजाए सीएमओ डॉ. गुलशन अरोड़ा ने फर्जीवाड़े का खेल शुरू कर दिया। अरोड़ा और उनके मुंहलगे डॉक्टर और कर्मचारी इन क्लीनिकों को कागजों में चलाते रहे। लेकिन इनकी यह धोखाधड़ी उस समय उजागर हुई जब पंचकुला स्थित मुख्यालय से संदेश आया कि 21 दिसंबर को टीम क्लीनिक का दौरा करने आ रही है।

अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए डॉ. अरोड़ा और उनकी टीम ने नया खेल शुरू कर दिया। 20 दिसंबर को डीईआईसी सेन्टर के एक कमरे के बाहर एनसीडी क्लीनिक का बोर्ड लगवा दिया। उन्होंने बीके अस्पताल के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. दिनेश रंगा व अन्य डॉक्टर और कर्मचारियों की तैनाती फर्जी तरीके से इस क्लीनिक में दर्शा दी। इतना ही नहीं दौरा करने के लिए आने वाली टीम को दिखाने के लिए रातों रात एक रजिस्टर भी तैयार कर दिया। इस रजिस्टर के मुताबिक क्लीनिक में हर रोज 25 से 30 मरीजों के आने की एंट्री भी दिखा दी।

एनसीडी क्लीनिक की प्रभारी दांतों की डॉ. सीमा ने तो झूठ बोलने की सभी हदों को पार करते हुए दावा किया है कि क्लीनिक अप्रैल 2017 से शुरू हो गया था। इसमें रोजाना 25 से 30 मरीजों की जांच की जा रही है। जिसमें 30 वर्ष से ऊपर की उम्र के ज्यादा मरीज अपनी जांच के लिए रोजाना आ रहे है। डॉ. सीमा का दावा है कि फिलहाल यहां रोजाना बीपी, शूगर की जांच की जा रही है।